Azim Premji University

भारतीय सन्दर्भ में मूल्यांकन के उद्देश्य की बारीक पड़ताल

भारतीय सन्दर्भ में मूल्यांकन के उद्देश्य की बारीक पड़ताल[i]

प्रस्तावना

किसी कक्षा में विद्यार्थी द्वारा शिक्षक से पूछे गए सवाल से लेकर बड़े पैमाने के मानकीकृत टेस्ट तक – शैक्षणिक मूल्यांकन का दायरा काफ़ी विस्तृत हो सकता है। यह प्रकाश संश्लेषण की अवधारणा अथवा दो संख्याओं के जोड़ के बारे में किसी शिक्षक द्वारा पूछा गया सवाल हो सकता है या फिर यह किसी ख़ास वैज्ञानिक तथ्य को समझने के लिए दो विद्यार्थियों के बीच हो रहा परस्पर संवाद हो सकता है। मूल्यांकन सतत व अनौपचारिक भी हो सकता है और औपचारिक व नियमित भी – मसलन, किसी पाठ के अंत में दिया गए प्रश्न, या वार्षिक परीक्षा या मानकीकृत उपलब्धि टेस्ट। इन सभी स्थितियों में मूल्यांकन का उद्देश्य अलग-अलग होता है और इसे एक ऐसी गतिविधि की तरह देखा जा सकता है जिससे यह सूचना मिलती है कि अपेक्षित शैक्षणिक परिणामों की तुलना में विद्यार्थी की क्या स्थिति है।

इन विविध उद्देश्यों के साथ किया गया मूल्यांकन शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्कूली शिक्षा विद्यार्थियों में कुछ विशिष्ट ज्ञान, कौशल और प्रवृत्तियाँ विकसित करने कोशिश करती है जो शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों से निर्देशित होते हैं। गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा से विद्यार्थियों को ऐसे साधन व अवसर मिलने चाहिए जिससे वे शिक्षा के इन उद्देश्यों को हासिल करने में सक्षम बन सकें। मूल्यांकन से शिक्षा के सभी साझेदारों को ऐसी उपयोगी सूचना मिलती है जिससे वे यह समझ सकें कि विद्यार्थियों को जो साधन व अवसर उपलब्ध कराए गए हैं वे उनमें इच्छित ज्ञान, कौशल व प्रवृत्तियाँ विकसित करने में सहायक रहे हैं या नहीं।

पिछले कुछ दशकों में मूल्यांकन का इस्तेमाल कई उद्देश्यों के लिए किया गया है। व्यवहार में इन अलग-अलग उद्देश्यों में काफ़ी कुछ मिलता-जुलता है। इस संदर्भ में कुछ सवाल महत्त्वपूर्ण हैं: समाज की बदलती ज़रूरतों के मुताबिक़ मूल्यांकन के तौर-तरीकों में कैसे बदलाव आए हैं; गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में मूल्यांकन की क्या भूमिका होती है और क्या किसी एक उद्देश्य के लिए बना मूल्यांकन किसी दूसरे उद्देश्य के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? ऐसे में, पहले मूल्यांकन के वास्तविक उद्देश्य को चिह्नित करना उपयोगी रहेगा और उसके

बाद ऐसे मूल्यांकन विकसित किए जा सकते हैं जिससे विद्यार्थियों के सीखने को बेहतर बनाने में मूल्यांकन की असली शक्ति का इस्तेमाल किया जा सके। इस पर्चे की चर्चा स्कूली शिक्षा के सीनियर सेकेण्डरी या उच्चतर माध्यमिक स्तर तक सीमित है। मूल्यांकन के सभी उद्देश्यों को भारतीय संदर्भ से लिए उदाहरणों के ज़रिए समझाया गया है। इस पर्चे में मूल्यांकन के हर उद्देश्य की सीमाओं व चुनौतियों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। साथ ही हर उद्देश्य की चर्चा उसकी कार्य, पद्धति, नज़रिए, उपयोग का समय, इस्तेमाल के तरीक़ों, सीमाओं और साझेदारों को ध्यान में रखते हुए की गई है।

प्रमाणन के लिए मूल्यांकन (Assessment for certification)

प्रमाणन के लिए किए जाने वाले मूल्यांकनों का स्वरूप औपचारिक होता है और ये किसी प्रमाणन संस्थान (Accreditation body) द्वारा किए जाते हैं। ये मूल्यांकन यह प्रमाणित व पुष्ट करते हैं कि विद्यार्थी ने किसी खास तरह का ज्ञान, कौशल व प्रवृत्तियों को हासिल कर लिया है। उपलब्धि का प्रमाणन गुणवत्ता के मानक का काम करता है और शिक्षा के अगले स्तर पर जाने का रास्ता खोलता है। इसमें मुख्यतः किसी एक स्तर पर हासिल किए गए क्रेडिट्स अगले स्तर में स्थानान्तरित हो जाते हैं उदाहरण के लिए, सेकेण्डरी या माध्यमिक स्तर (दसवीं कक्षा) तक हासिल किए गए क्रेडिट्स उच्च माध्यमिक/स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में स्थानान्तरित हो जाते हैं। भारत में दसवीं व बारहवीं के प्रमाणन के मूल्यांकन आमतौर पर लिखित रूप में किए जाते हैं और ये विद्यार्थियों के लिए पहली बाह्य परीक्षाएँ होती हैं। दसवीं कक्षा के प्रमाणन मूल्यांकनों को अक्सर 'शाला त्याग परीक्षा' (स्कूल लीविंग एग्जामिनेशन) भी कहा जाता है। हमारे देश में तीन राष्ट्रीय बोर्ड हैं – केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेण्डरी एजुकेशन (सीबीएससी) काउन्सिल फ़ॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (सीआइएससीई) और नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस)। इसके अलावा राज्यों के बोर्ड हैं जो दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएँ आयोजित करती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफ़ारिश है कि हर राज्य में शाला-त्याग प्रमाणपत्र के लिए मूल्यांकन करने और इसका प्रमाणन करने के लिए एक या एक से ज़्यादा बोर्ड हो सकते हैं। इनमें से एक सीबीएसई हो सकता है।

प्रमाणन मूल्यांकन के ज़रिए क्रेडिट स्थानान्तरण के कार्य के अलावा दसवीं कक्षा की परीक्षा के नतीजों व पास प्रतिशत के आधार पर अभिभावक किसी स्कूल की प्रतिष्ठा का अन्दाज़ा भी लगाते हैं। इसके अलावा, प्रमाणन परीक्षा के नतीजों का इस्तेमाल किसी क्षेत्र विशेष में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का पूर्वानुमान लगाने के लिए भी किया

जाता है। इस तरह ये किसी ख़ास नौकरी के लिए किसी विद्यार्थी के चयन या अस्वीकृति के मापदण्ड की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। यह माना जाता है कि जिन विद्यार्थियों के अंक अच्छे होते हैं उनमें दस साल की स्कूली शिक्षा के बाद ज्ञान, कौशल और प्रवृत्तियों का स्तर ज़्यादा बेहतर होता है और उनके किसी क्षेत्र में सफल होने की सम्भावना भी ज़्यादा होती है (लेस्टर, एरहार्ड्ट व स्टैंडिफर 2016)।

इस तरह के मूल्यांकन का स्वरूप योगात्मक (summative) होता है और यह अकादमिक वर्ष के अन्त में किया जाता है। बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्नपत्र व्यवस्थित व गोपनीय प्रक्रिया से बनाए जाते हैं। प्रश्नपत्र बनाने वाले एक मानकीकृत प्रक्रिया से मूल्यांकन किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं की पहचान करते हैं, एक सन्तुलित खाका बनाते हैं जिसमें विविध प्रकार की संज्ञानात्मक कुशलताओं के मूल्यांकन पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है और इस खाके के अनुरूप सवाल विकसित करते हैं। इन मूल्यांकनों को मापदण्ड संदर्भित (criterion referenced) माना जाता है, क्योंकि इनमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के पूर्वनिर्धारित उद्देश्यों के संदर्भ में किया जाता है। इन मूल्यांकनों का उद्देश्य विद्यार्थियों की एक-दूसरे से तुलना करना नहीं होता है। परीक्षा में नक़ल रोकने के लिए अक्सर प्रश्न पत्रों के एक से ज़्यादा सेट होते हैं। चूँकि उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच केन्द्रीकृत होती है इसलिए हर सवाल के लिए मानकीकृत मार्किंग योजना भी विकसित की जाती है।

बोर्ड परीक्षाएँ विद्यार्थियों के लिए ख़ासी महत्त्वपूर्ण होती हैं क्योंकि इनके नतीजों से ही यह तय होता है कि विद्यार्थी आगे की शिक्षा या करियर के लिए क्या चुनाव कर सकते हैं। ये परीक्षाएँ स्कूल में कई वर्षों तक चलने वाली सीखने की पूरी प्रक्रिया का चरम बिन्दु होती हैं। इस तरह वर्षांत में होने वाले ये मूल्यांकन विद्यार्थियों में बेहद तनाव की वजह बनते हैं और यह पूरी तरह उचित नहीं है। इस ग़ैरज़रूरी तनाव व भय को देखते हुए ही नई शिक्षा नीति यह सिफ़ारिश करती है कि बोर्ड परीक्षाओं को ख़त्म कर के उनकी जगह हर विषय के लिए मॉड्यूलर मूल्यांकन की व्यवस्था होनी चाहिए जो 9वीं से 12वीं कक्षा के बीच कभी भी किया जा सके।

इसके अलावा, बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे महज़ विद्यार्थी के सीखने और उसके प्रदर्शन का मापक ही नहीं होते हैं। इनसे यह भी पता चलता है कि स्कूली शिक्षा कितनी प्रभावोत्पादक रही। दुर्भाग्य से, विद्यार्थी सिर्फ़ गणित, विज्ञान, भाषा व सामाजिक विज्ञान जैसे कुछ विषयों पर ही ध्यान देते हैं जिनसे उनको बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा अंक पाने में मदद मिलती है। हालाँकि कला व व्यावसायिक शिक्षा के विषय भी पाठ्यचर्या का हिस्सा होते हैं लेकिन बोर्ड परीक्षा में उनके लिए कोई अंक नहीं होता है। इस वजह से विद्यार्थी इनकी बजाय उन विषयों पर ही ध्यान देते हैं जिनसे बोर्ड परीक्षा के अंकों पर प्रभाव पड़ता है।

चूँकि इन परीक्षाओं में बहुत कुछ दाँव पर लगा होता है, इसलिए विद्यार्थी अक्सर सीखने की प्रक्रिया को मूल्यांकन में पूछे जाने वाले सवालों तक सीमित कर देते हैं। इस वजह से उनका ध्यान वास्तविक समझ, विचार, विश्लेषण व व्यवहार से हट जाता है (नई शिक्षा नीति 2020)। इन परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन अप्रत्यक्ष रूप से उनके शिक्षकों के प्रदर्शन, वेतन और नौकरी की निश्चितता से भी जुड़ा होता है (बेकर, बार्टन, डार्लिंग-हॉमण्ड, हार्टेल, लैंड, लिन्न व शेपर्ड, 2010)। इसकी वजह से अक्सर यह ख़तरा पैदा हो जाता है कि शिक्षक महज़ परीक्षा के लिए शिक्षण करने लगें; वे महज़ इस बात पर ही ध्यान देने लगें कि मानकीकृत परीक्षाओं में विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करें; शिक्षा के उच्चतर उद्देश्यों को हासिल करने पर ध्यान ही न दें और वे पाठ्यपुस्तक को याद रखने व उसे ज़रूरत पड़ने पर उगल देने तक ही विद्यार्थियों के ज्ञान को सीमित कर दें।

चयन के लिए मूल्यांकन (Assessment for selection)

इस तरह का मूल्यांकन किसी कोर्स या छात्रवृत्ति या रोज़गार के लिए विद्यार्थियों के चयन में मदद करता है – यानी ये उपयुक्त व्यक्ति अंदर और अनुपयुक्त बाहर की परिपाटी पर चलता है। यह इसका भी एक उदाहरण है कि किसी विद्यार्थी को आगे की पढ़ाई से कितना लाभ मिलेगा या किसी रोज़गार में उसका प्रदर्शन कैसा होगा यह पूर्वानुमान लगाने के लिए मूल्यांकन का उपयोग किस तरह किया जाता है।

स्कूली शिक्षा में हमारे यहाँ दो तरह के चयन मूल्यांकन होते हैं — छात्रवृत्तियों के लिए होने वाला मूल्यांकन और ऊँची कक्षा/अध्ययन के लिए प्रवेश परीक्षा। भारत में स्कूली स्तर पर कई तरह की सरकारी व निजी छात्रवृत्तियाँ हैं। मसलन, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन (एनटीएससी), सीबीएससी एकल बालिका छात्रवृत्ति और इसरो बाल वैज्ञानिक कार्यक्रम। इन छात्रवृत्ति परीक्षाओं को पास करने पर ट्यूशन फ़ीस में छूट, मुफ़्त पुस्तकें, उच्च शिक्षा की फ़ीस में मदद जैसी सुविधाएँ विद्यार्थियों को मिलती हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति फंड की स्थापना की जाएगी जिसमें से ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह सहायता स्टायपेंड, आवास व भोजन खर्च व ट्यूशन फ़ीस में छूट के रूप में प्रदान की जाएगी। इसके अलावा दूसरी तरह का चयन मूल्यांकन 12वीं कक्षा के बाद अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में दाख़िले के लिए किया जाता है, मसलन, इंजीनियरिंग के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम (जेईई), वास्तुकला के लिए नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर (एनएटीए), क़ानून के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीलैट), और चिकित्सा के लिए नेशनल इलेजिबिल्टी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) आदि।

एक बार फिर, इनके प्रश्नपत्रों को बनाने के लिए एक मानकीकृत पद्धति अपनाई जाती है। इसमें प्रश्नपत्र उस अकादमिक विषय या कार्य के उद्देश्यों के अनुरूप बनाया जाता है जिसे हासिल करने की इच्छा विद्यार्थी में है। यहाँ चुनौती होती है एक ऐसा वैध व विश्वसनीय प्रश्नपत्र बनाने की जो चयन के निर्णयों में मददगार साबित हो (ब्रुकहार्ट व निटको, 2014)। पहला, उन बिन्दुओं को चिह्नित करना जिनकी ज़रूरत भावी अकादमिक अध्ययन में पड़ेगी और फिर एक ऐसा प्रश्नपत्र बनाना जिससे उन बिन्दुओं का आदर्श मूल्यांकन किया जा सके और दूसरा, आदर्श स्थिति में इस मूल्यांकन में विद्यार्थी का प्रदर्शन उस कार्यक्रम में विद्यार्थी के प्रदर्शन के अनुपात में होना चाहिए। किसी चयनित विद्यार्थी के उस कार्यक्रम में असफल होने की सम्भावना (विभिन्न परिस्थितियों की वजह से, जिनको जाना नहीं जा सकता) अनिश्चित होती है व उसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है।

इस तरह का मूल्यांकन टेस्ट में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर उनको योग्यता के क्रम में श्रेणीबद्ध करता है। इस तरह यह एक नियम-संदर्भित (norm-referenced) मूल्यांकन होता है। यहाँ पर उद्देश्य विभिन्न विद्यार्थियों की आपस में तुलना करके उनके बीच अंतर करना है। विद्यार्थियों की बड़ी संख्या के भाग लेने से ऐसे मूल्यांकनों में उनका प्रदर्शन 'बेल कर्व' (फ़्रीमैन व लूईस, 1998) का रूप लेता है। यह एक मान्यता है कि ऐसे मूल्यांकन में ज़्यादातर विद्यार्थी औसत मान के आसपास ही रहेंगे और बची हुई छोटी संख्या में से कुछ का प्रदर्शन औसत से ऊपर और कुछ का उससे नीचे होगा। दूसरे शब्दों में, इस मान्यता के अनुसार कुछ विद्यार्थियों का असफल होना निश्चित है जबकि कुछ उपलब्धि के उच्चतम स्तर तक पहुँचेंगे। नियम-संदर्भित मूल्यांकन के इस बुनियादी स्वभाव की वजह से, यह सिर्फ़ चयन के लिए लिए ही उपयुक्त होता हैं। कक्षा-आधारित मूल्यांकन मापदण्ड-संदर्भित होते हैं। इसका अर्थ है कि मूल्यांकन को सीखने की उपलब्धियों से जुड़े मापदण्डों से समायोजित किया जाता है और यहाँ मान्यता यह होती है कि सभी विद्यार्थी सीखने की यह उपलब्धियाँ हासिल कर सकते हैं।

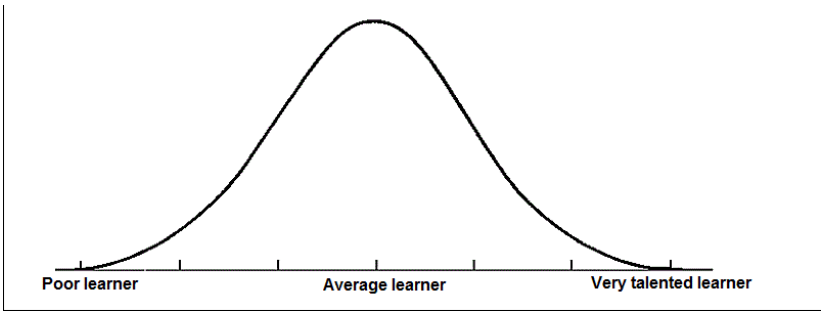

चित्र 1 - नियम-संदर्भित मूल्यांकन में अंकों का सामान्य वितरण

शिक्षण व शिक्षार्जन में सहयोग करने वाला मूल्यांकन

(Assessment to support teaching and learning)

इस तरह का मूल्यांकन स्कूली शिक्षा में हमेशा से हावी रहा है। इस मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण कार्यक्रमों, पाठ्यचर्या व शिक्षण में सुधार के ज़रिए विद्यार्थियों के सीखने में व्यवस्थित सुधार लाना होता है (गैग्ने व बियर्ड, 1978)। यह मूल्यांकन जिन तीन बुनियादी सवालों को सम्बोधित करता है, वे हैं, (1) हम अपने विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहते हैं? (2) विद्यार्थी सीख रहे हैं इसके प्रमाण हम कैसे इकट्ठा करें? और (3) विद्यार्थी इच्छित नतीजों को कहाँ तक हासिल कर सके हैं? चित्र 2 में दिए गतिशील शिक्षण-शिक्षार्जन चक्र का इस्तेमाल करके इन सवालों को ज़्यादा बेहतर समझा जा सकता है।

इस चक्र में पहला चरण है सीखने के ऐसे परिणामों का विकास व उनकी समझ जो यह दिखाते हों कि उस विषय/अध्याय/यूनिट/कोर्स को पूरा करने के बाद विद्यार्थी को क्या ज्ञान होगा या वह क्या कर सकेगा। शिक्षण पद्धतियों, सीखने की गतिविधियों और हर विषय में अवधारणाओं के सफलतापूर्वक लेनदेन के लिए मूल्यांकन योजनाएँ निर्धारित करने में सीखने के प्रतिफलों की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। सीखने के प्रतिफल (या अधिगम प्रतिफल) को किसी कक्षा में विद्यार्थी के सीखने के अपेक्षित स्तर का संकेत देने वाले मूल्यांकन मापदण्डों के रूप में परिभाषित किया जाता है (भारत सरकार, 2017)। सीखने के परिणामों की स्पष्ट समझ होने से शिक्षकों को मूल्यांकन की योजना बनाने, उसका आयोजन करने और इस्तेमाल करने में मदद मिलती है।

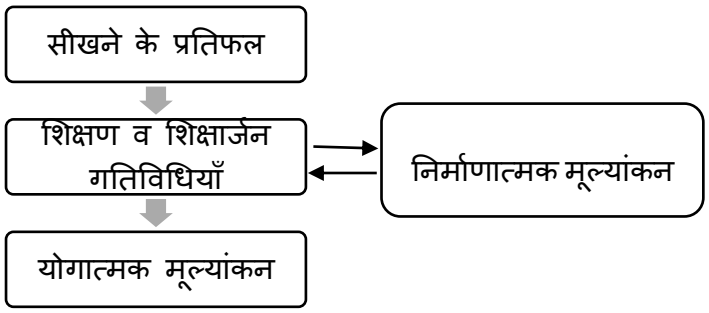

चित्र 2: गतिशील शिक्षण-शिक्षार्जन चक्र

दूसरा चरण है सीखने के इन प्रतिफलों को हासिल करने में विद्यार्थियों की मदद करने के लिए उपयुक्त शिक्षण व शिक्षार्जन गतिविधियों का विकास। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण-शिक्षार्जन प्रक्रिया से एकीकृत होता है और इसका आयोजन सीखने की पूरी प्रक्रिया में किया जाता है। इसका उपयोग विद्यार्थियों को फ़ीडबैक देकर सीखने की प्रक्रिया में उनकी मदद देने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल उनकी शक्तियों व कमज़ोरियों को चिह्नित

करने के लिए और सीखने में सुधार के लिए ज़रूरी मदद देने के लिए किया जा सकता है। इसीलिए इस तरह के मूल्यांकन को सीखने के लिए मूल्यांकन भी कहते हैं। चूँकि इन मूल्यांकनों में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को अलग-अलग श्रेणियों में नहीं रखा जाता इसलिए इनमें विद्यार्थियों के लिए उतना कुछ दाँव पर नहीं लगा होता।

रचनात्मक मूल्यांकन में शिक्षक के साथ-साथ विद्यार्थी भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वह मूल्यांकन जो विद्यार्थी ख़ुद करते हैं उसे स्व-मूल्यांकन कहा जाता है। यह रचनात्मक मूल्यांकन की ही एक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी अपने काम की गुणवत्ता पर चिंतन-मनन करते हैं (स्व-निगरानी), इसका निर्णय लेते हैं कि वह स्पष्ट उल्लिखित अधिगम परिणामों के कितना क़रीब है (स्व-निर्णय) और इसके आधार पर वे अपने काम में सुधार लाते हैं (स्व-संशोधन) (गिप्स, 1999)। स्व-मूल्यांकन में मेटाकॉग्निशन (metacognition) की केन्द्रीय भूमिका होती है; इसमें विद्यार्थी विशिष्ट संज्ञानात्मक कुशलताओं पर सचेत रूप से अपना नियंत्रण बनाता है। उदाहरण के लिए, अपनी समझ का परीक्षण, नतीजों का पूर्वानुमान, गतिविधियों की योजना, समय का प्रबंधन और सीखने की विभिन्न गतिविधियाँ आज़माना। शिक्षक से मिली ज़रूरी मदद से स्वयं करके सीखने की प्रक्रिया मे शामिल होकर विद्यार्थी सीखने को लेकर ज़्यादा अभिप्रेरित व उत्साहित अनुभव करते हैं। इस स्थिति में, चूँकि मूल्यांकन सीखने के साथ-साथ ही होता है इसलिए इसे शिक्षार्जन के लिए मूल्यांकन भी कहते हैं।

तीसरा चरण है अधिगम परिणामों की उपलब्धि को मापने के लिए एक योगात्मक मूल्यांकन करना और उसके नतीजों को विद्यार्थियों, अभिभावकों व प्रशासकों तक पहुँचाना। कक्षा में यह आमतौर पर किसी विषय/अध्याय/यूनिट/कोर्स की समाप्ति पर किया जाता है, और इसे सीखने का मूल्यांकन भी कहते हैं। योगात्मक मूल्यांकन शिक्षकों द्वारा विकसित किया जाता है और वे ही इसे आयोजित भी करते हैं। आमतौर पर इनका इस्तेमाल विद्यार्थियों को अंक या ग्रेड देने के लिए किया जाता है इसलिए इसमें विद्यार्थियों का काफ़ी कुछ दाँव पर लगा रहता है।

योगात्मक मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन की कई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें टेस्ट, गतिविधियाँ, प्रोजेक्ट व वर्कशीट शामिल होते हैं। भारतीय स्कूलों में योगात्मक मूल्यांकन के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीक़ा है टेस्ट लेना। यह संक्षिप्त प्रश्नपत्रों के ज़रिए लिखित में या मौखिक रूप से लिया जाता है और इससे विद्यार्थी की निपुणता का अंदाज़ा लगता है। शिक्षक ख़ुद ही इनके उत्तर पत्रों की जाँच करते हैं और उत्तर सही होने के आधार पर अंक देते हैं। इसमें विद्यार्थी के प्रदर्शन को एक मात्रात्मक मूल्य देकर उसका मापन किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन में किसी निश्चित बिन्दु तक (मिड टर्म या एंड टर्म) सीखने के सभी प्रमाणों को संकलित कर दिया जाता है ताकि अंकों या ग्रेड पर आधारित मूल्यांकन की मदद से विद्यार्थी के अधिगम स्तर के बारे में कोई निर्णय लिया जा सके।

योगात्मक व रचनात्मक दोनों प्रकार के मूल्यांकन मापदण्ड-संदर्भित होते हैं यानी ये इस तरह बनाए जाते हैं जिनसे यह समझा जा सके कि विद्यार्थी कितना सीख सके हैं। इस तरह के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किसी समूह में विद्यार्थियों को एक-दूसरे की तुलना में रख कर देखने की बजाय विद्यार्थी को फ़ीडबैक देना होता है। रचनात्मक मूल्यांकन की स्थिति में सहयोगी माहौल बनाने के लिए और योगात्मक मूल्यांकन की स्थिति में घोषित अधिगम परिणामों की तुलना में विद्यार्थियों का अधिगम स्तर बताने के लिए यह मूल्यांकन उपयोगी होता है|

अधिगम प्रतिफल, शिक्षण-शिक्षार्जन गतिविधियों और मूल्यांकन में सामंजस्य होने की स्थिति में विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। निर्माणात्मक व योगात्मक, दोनों तरह के मूल्यांकनों की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन से यह पता लगाने में मदद मिलती है कि शिक्षण-शिक्षार्जन गतिविधियों से विद्यार्थियों को अधिगम के परिणाम हासिल करने में मदद मिली या नहीं। योगात्मक मूल्यांकन से यह मापने में मदद मिलती है कि विद्यार्थी अधिगम परिणाम किस स्तर तक हासिल कर सके हैं जिससे सीखने का एक सूचकांक मिलता है। रचनात्मक मूल्यांकन पर अधिक ज़ोर देने से योगात्मक मूल्यांकन में प्रदर्शन बेहतर होगा।

जवाबदेही के लिए मूल्यांकन (Assessment for accountability)

स्कूली शिक्षा की प्रभावोत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए निश्चित अंतराल पर मूल्यांकन की व्यवस्था होनी चाहिए – सिर्फ़ विद्यार्थियों के मूल्यांकन की ही नहीं बल्कि समूची शैक्षणिक प्रक्रिया के मूल्यांकन की भी। इस तरह के मूल्यांकन अगर सही तरीक़े से किए जाएँ तो इनसे शैक्षणिक प्रक्रिया के स्वास्थ्य सूचकांकों को जाँचने में मदद मिलती है और अगर उसमें कोई ख़ामी दिखाई दे तो संरचनागत स्तर पर हस्तक्षेप और सुधारात्मक कार्यवाही की जा सकती है। बड़े पैमाने के मूल्यांकन ठीक वही उपकरण हैं जिनसे शिक्षा प्रणाली को अपनी सेहत व प्रभावोत्पादकता के बारे में विचार करने का मौक़ा मिलता है।

किसी ज़िले, राज्य या देश भर में विद्यार्थियों की एक बड़ी संख्या को इस मूल्यांकन में शामिल किया जाता है – इसके लिए विद्यार्थियों के एक प्रतिनिधि सैंपल का चयन किया जाता है। इनका आयोजन राज्य, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। इस तरह के मूल्यांकनों का मुख्य उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना होता है – यानी यह कि जो इनपुट हैं (शिक्षण-शिक्षार्जन, स्कूली सुविधाएँ, पाठ्यचर्या, कार्यक्रम वग़ैरह) उनसे सही आउटपुट (विद्यार्थियों का प्रदर्शन व परिणाम) निकल रहे हैं या नहीं । चूँकि इस तरह के टेस्ट विद्यार्थियों की एक बड़ी संख्या के बीच किए जाते हैं इसलिए ये ज़्यादातर बहु-वैकल्पिक प्रश्नों के रूप में होते हैं जिनका स्वचालित

(ऑटोमैटिक) मूल्यांकन किया जा सके। आमतौर पर यह टेस्ट स्कूली शिक्षा के एक चरण से दूसरे चरण के संक्रमण के किसी महत्त्वपूर्ण पायदान पर लिए जाते हैं। मिसाल के लिए, पूर्व-प्राथमिक से प्राथमिक – तीसरी कक्षा, प्राथमिक से उच्च-प्राथमिक – पाँचवीं कक्षा, उच्च प्राथमिक से सेकेण्डरी – आठवीं कक्षा, और सेकेण्डरी से हायर सेकेण्डरी – दसवीं कक्षा। संक्रमण के चरण में इस तरह के टेस्ट से विद्यार्थियों के अधिगम स्तर और उपयुक्त सुधारात्मक कार्यवाही का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये टेस्ट मानकीकृत होते हैं यानी इनकी विषयवस्तु, सवाल और अंक पाने की प्रक्रिया, आयोजन का तरीक़ा और टेस्ट के नतीजों की व्याख्या में एकरूपता होती है। एकरूपता से देश के विभिन्न हिस्सों में विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना करना सम्भव होता है। आमतौर पर ऐसे मूल्यांकन वार्षिक होते हैं जिससे विद्यार्थियों के वर्तमान अधिक स्तर की जानकारी मिल सके और समय के साथ उनमें हो रहे सम्भावित बदलावों पर नज़र रखना भी सम्भव हो।

अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन किसी शिक्षा प्रणाली की तुलना एक या एक से अधिक शिक्षा प्रणालियों से करके उसके बारे में जानकारी देते हैं। इन मूल्यांकनों से शिक्षा की वैश्विक प्रवृत्तियों और उभरती प्रणालियों को समझने में मदद मिलती है। अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन के नतीजों का इस्तेमाल देश अपनी शिक्षा प्रणाली के विश्लेषण के लिए करते हैं। प्रोग्रॉम फ़ॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट (Programme for International Student Assessment–PISA) 15 वर्ष तक के विद्यार्थियों में पठन, गणित व विज्ञान के सीखने के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए तीन साल में एक बार किया जाता है। भारत में यह टेस्ट अब तक सिर्फ़ एक बार 2009 में किया गया है।

राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकनों का उद्देश्य होता है विभिन्न राज्यों, अंचलों (शहरी/ग्रामीण), प्रशासनिक चक्रों में हर विषय की विषयवस्तु व उससे जुड़े कौशल को कक्षा-वार अधिगम परिणामों के संदर्भ में रख कर जाँचना और उनमें दीर्घकालीन प्रवृत्तियों को चिह्नित करना (शिक्षा मंत्रालय, 2017)। राज्य-स्तरीय मूल्यांकनों से शिक्षकों, प्रशासकों, स्कूलों व ज़िलों के प्रदर्शन को स्थापित अधिगम परिणामों के संदर्भ में रखकर देखने का मौक़ा मिलता है। इनसे किसी विषय से जुड़ी किसी ख़ास विषयवस्तु या कौशल में मज़बूतियों या कमज़ोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है, जिसका इस्तेमाल शिक्षण-शिक्षार्जन में उपयुक्त बदलाव लाने के लिए किया जाता है।

भारत में ऐसे अनेक मूल्यांकन राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर किए जाते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) हर साल देश भर में नेशनल एचीवमेंट सर्वे (NAS) का आयोजन करता है। इस टेस्ट में देश के सभी ज़िलों के सरकारी व सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों के एक प्रतिनिधि नमूने को शामिल किया जाता है। टेस्ट में तीसरी, पाँचवीं, आठवीं और दसवीं कक्षा के भाषा, पर्यावरण विज्ञान, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। एनुअल स्टेटस ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट (ASER) नागरिकों के नेतृत्व में किया जाना

वाला दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू सर्वेक्षण है जिसका आयोजन प्रथम नाम की संस्था करती है। इसमें 6-14 साल तक के बच्चों का मूल्यांकन साक्षरता व अंक क्षमता के लिए किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय	**राष्ट्रीय**	**राज्य-स्तरीय**
प्रोग्रेस इन इंटरनेशनल रीडिंग लिटरेसी स्टडी (PIRLS)	नेशनल एचीवमेंट सर्वे (NAS)	सेंसस स्टेट एचीवमेंट सर्वे (CSAS) - कर्नाटक
ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथमैटिक्स एंड साइंस स्टडी (TIMSS)	एनवल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (ASER)	गुणोत्सव – गुजरात
प्रोग्राम फ़ॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेंसमेंट (PISA)		प्रतिभा पर्व – मध्य प्रदेश

चित्र 3: भारत में किए जाने वाले बड़े स्तर के मूल्यांकन

इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफ़ारिश है कि हर राज्य में गणना-आधारित राज्य मूल्यांकन सर्वे (census-based State Assessment Survey — SAS) किए जाने चाहिए। विकासात्मक उद्देश्यों से किए जाने वाले ऐसे सर्वे से राज्यों में जवाबदेही स्थापित करने की योजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन सम्भव होगा और यह भी पता चलेगा कि राज्य में किस तरह का मूल्यांकन सबसे बेहतर काम कर रहा है। कर्नाटक में चौथी से दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए गणना-आधारित राज्य उपलब्धि सर्वे (Census-based State Achievement Survey — CSAS) का आयोजन हर साल कर्नाटका स्टेट क्वालिटी एसेसमेंट एण्ड एक्रेडिटेशन काउंसिल (KSQAAC) द्वारा किया जाता है। आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर और पंजाब में राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् (SCERT) द्वारा प्रारम्भिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए हर साल विद्यार्थी-स्तरीय उपलब्धि सर्वे (Student Level Achievement Survey – SLAS) का आयोजन किया जाता है। दूसरी से पाँचवीं कक्षा के विद्यार्थियों में पठन, लेखन व अंक कुशलता के मूल्यांकन के लिए गुजरात शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् (GCERT) गुणोत्सव का आयोजन करता है। मध्य प्रदेश में राज्य शिक्षा केन्द्र प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रतिभा पर्व का आयोजन करता है।

अच्छी तरह से बनाए गए और उपयुक्त तरीक़े से इस्तेमाल किए गए मूल्यांकन स्कूली शिक्षा के परिणामों के बारे में सूचना देने का काम करते हैं। इनसे नीति निर्माता, प्रशासक, स्कूल व शिक्षक यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर विद्यार्थी को स्थापित अधिगम परिणाम हासिल करने के लिए ज़रूरी सुविधाएँ मिल सके और साथ ही शिक्षण, पाठ्यचर्या व कार्यक्रमों के अन्य तत्वों में उपयुक्त संशोधन किए जा सकें। इस वजह से यह ज़रूरी है कि बड़े पैमाने के मूल्यांकनों की जानकारियाँ व अन्य सम्बन्धित सूचनाएँ इससे जुड़े साझेदारों से नियमित रूप से साझा की जाएँ ताकि उनका सरोकार, भागीदारी व सहयोग बना रहे। शिक्षण में सुधार के उद्देश्य से इन सूचनाओं की व्याख्या

करने के लिए शिक्षकों को पर्याप्त समय और सहयोग मुहैया कराना चाहिए। उनको ऐसी शिक्षण रणनीतियाँ इस्तेमाल करने के लिए मदद की जानी चाहिए जो सभी विद्यार्थियों में सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाएँ।

इस तरह के मूल्यांकन का अलग-अलग विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत रूप से कोई नैदानिक मूल्य नहीं होता क्योंकि यह विद्यार्थियों के एक नमूने के साथ किया जाता है और इसका स्वरूप मुख्यतः योगात्मक होता है और यह किसी टर्म के मध्य में या उसके अन्त में आयोजित किया जाता है। राज्य या जिला स्तरीय मूल्यांकन की रपट में विद्यार्थियों के अधिगम स्तर की जो व्यापक तस्वीर पेश की जाती है उससे किसी शिक्षक को यह तो पता चल सकता है कि किसी स्थान विशेष में ऐसे कौन से विषय या कौशल हैं जिनको लेकर ज़्यादातर विद्यार्थियों की समझ या सीखने में कमी है, लेकिन ऐसी रपट से किसी एक विद्यार्थी के सीखने के स्तर पर ध्यान देने में मदद नहीं मिलेगी। जैसा कि नई शिक्षा नीति 2020 में कहा भी गया है कि ऐसे मूल्यांकनों का इस्तेमाल व्यक्तिगत शिक्षकों, विद्यार्थियों और/या स्कूलों का मूल्यांकन या ग्रेडिंग करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, न ही उनका इस्तेमाल विद्यार्थियों या स्कूलों की लेबलिंग के लिए किया जाना चाहिए। चूँकि इन मूल्यांकनों से विद्यार्थियों के ग्रेड या अंक प्रतिशत पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता इसलिए इनमें उनका हित दाँव पर नहीं लगा होता है।

सार-संक्षेप

स्कूलों में मूल्यांकन के तौर-तरीकों को बेहतर बनाने की कई नीतिगत पहलकदमियों के बावजूद NAS व ASER जैसे जवाबदेही के उद्देश्य से किए गए मूल्यांकनों में विभिन्न कक्षाओं में विद्यार्थियों के सीखने के स्तर का औसत उनकी कक्षा के अपेक्षित अधिगम स्तर की तुलना में खराब पाया गया। सीखने के औसत स्तर बेहद ख़राब हैं और जैसे-जैसे विद्यार्थी प्राथमिक से उच्च प्राथमिक और उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर की तरफ़ बढ़ते हैं, उनके सीखने के स्तर में और भी कमी देखने को मिलती है (चोमल, बनर्जी, 2019)।

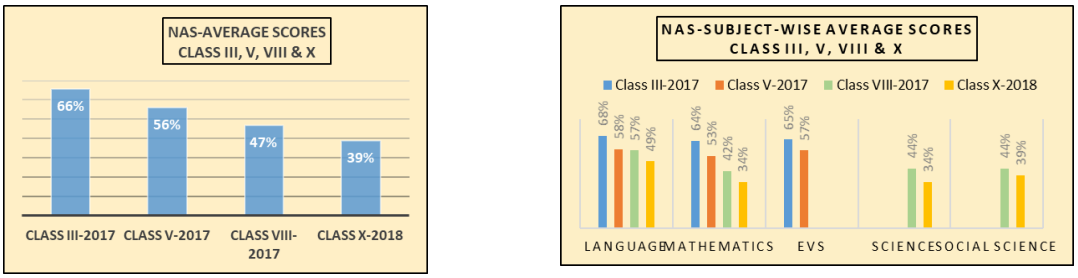

चित्र 4: NAS के औसत अंक और विषय-वार औसत अंक

निम्न औसत अधिगम स्तरों के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। इनमें कक्षा में शिक्षण-शिक्षार्जन की पद्धति, किस तरह की पाठ्यपुस्तकें इस्तेमाल की जा रही हैं और शिक्षकों की क्षमता में विकास की पहलकदमियों का अभाव जैसी वजहें शामिल हैं। कक्षा में मूल्यांकन जिस तरह से किया जाता है और सीखने में सुधार लाने के लिए जिस तरह से उनका इस्तेमाल होता है यह भी एक वजह है। भारत के कई राज्यों में ASER (सिन्हा, 2016) और TESS (मेक्कॉर्मिक, 2014) द्वारा सीसीई के क्रियान्वयन सम्बन्धी शोध अध्ययनों इस बात के भरपूर प्रमाण मिलते हैं कि मूल्यांकन का इस्तेमाल ज़्यादातर ग्रेडिंग के लिए किया जाता है और मूल्यांकनों का ज़ोर पाठ्यपुस्तकों को याद करके प्रस्तुत करने पर ही होता है। भारत के ज़्यादातर राज्यों में रचनात्मक मूल्यांकन आज भी छोटे-छोटे लिखित टेस्टों की एक श्रृंखला होते हैं और इन टेस्टों में मिले अंकों जोड़ कर विद्यार्थियों की ग्रेडिंग की जाती है। यह विचार लगभग नदारद है कि निर्माणात्मक टेस्टों के नतीजों का इस्तेमाल सीखने को बेहतर बनाने के लिए और अंत में योगात्मक टेस्ट के नतीजों को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है (राज, बनर्जी, 2019)। मूल्यांकन के केन्द्रीय उद्देश्य और उनके नतीजों का इस्तेमाल कर कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को बेहतर बनाने की कोशिश करने की स्पष्ट समझ का हमारी कक्षाओं में अभाव है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में मूल्यांकन के हर उद्देश्य की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। उसके उद्देश्य व इस्तेमाल के आधार पर सही प्रकार का मूल्यांकन विकसित करना ज़रूरी है। मूल्यांकन के उद्देश्य और उसके नतीजों के इस्तेमाल में विसंगति होने की स्थिति में मूल्यांकन का कोई मतलब नहीं रह जाता। मिसाल के लिए, जब प्रमाणन मूल्यांकन का इस्तेमाल विद्यार्थियों की रैंकिंग के लिए होता है, या रचनात्मक मूल्यांकन को ग्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज के दौर में जब मूल्यांकन में बहुत कुछ दाँव पर लगा हुआ है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर ध्यान देने का दबाव बहुत ज़्यादा है। स्व-मूल्यांकन को सिखाने, अनुभव करने व प्रोत्साहित करने पर मामूली ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ यह समझना ज़रूरी हे कि जवाबदेही, प्रमाणन, और चयन के लिए किए जाने वाले मूल्यांकनों में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तभी बेहतर होगा जब निर्माणात्मक मूल्यांकन का प्रयोग कक्षा में शिक्षा पद्धति, सीखने और मूल्यांकन के एकीकरण के लिए किया जाए। स्कूलों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को महज़ ख़ास तरह के मूल्यांकन के लिए न तैयार करें बल्कि शिक्षा के उच्च उद्देश्यों को हासिल करने के लिए उनको सार्थक शैक्षणिक अनुभव देकर जीवन के लिए तैयार करें।

मूल्यांकन का उद्देश्य	कार्य	परिणामों का इस्तेमाल	मूल्यांकन कब होता है	मूल्यांकनकर्ता	साझेदार	मूल्यांकन की प्रकृति	विद्यार्थी का कितना हित जुड़ा है	सीमा
जवाबदेही	शिक्षा प्रणाली की सेहत की समझ बनाना	व्यवस्थागत सुधार के कदम उठाना	समय-समय पर	केन्द्र व राज्य सरकार, एनजीओ	नीति निर्माता पाठ्यचर्या का विकास करने वाले प्रशासक टीचर एजुकेटर शिक्षक	नियम-संदर्भित	निम्न	नैदानिक मूल्य नहीं होता
प्रमाणन	विशिष्ट ज्ञान, कौशल वप्रवृत्तियों की उपलब्धि का प्रमाणन	क्रेडिट स्थानांतरण, विद्यार्थी के प्रदर्शन का पूर्वानुमान	कक्षा 10/कक्षा 12 के अंत में	परीक्षा बोर्ड	नीति निर्माता पाठ्यचर्या का विकास करने वाले प्रशासक टीचर एजुकेटर शिक्षक अभिभावक विद्यार्थी	मापदण्ड-संदर्भित	अति उच्च	टेस्ट के लिए शिक्षण व शिक्षार्जन
चयन								
छात्रवृत्ति	वित्तीय लाभ मुहैया कराना	छात्रवृत्ति मुहैया कराना	कोई भी कक्षा	छात्रवृत्ति देने वाली संस्था	अभिभावक विद्यार्थी	नियम-संदर्भित	उच्च	मात्र एक मूल्यांकन पर आधारित
प्रवेश	भावी कोर्स में विद्यार्थी के प्रदर्शन का पूर्वानुमान	उच्च शिक्षा के लिए चयन	कक्षा 12 के बाद	उच्च संस्थान	संस्थान विद्यार्थी	नियम-संदर्भित	उच्च	मात्र एक मूल्यांकन पर आधारित
शिक्षण व शिक्षार्जन में सहयोग								
सीखने का मूल्यांकन	अधिगम परिणामों की उपलब्धि का मापन	ग्रेडिंग व रिपोर्टिंग	अध्याय/यूनिट/ साल के अंत में	शिक्षक	प्रशासक अभिभावक शिक्षक विद्यार्थी	नियम-संदर्भित	उच्च	सुधार की कोई गुंजाइश नहीं
सीखने के लिए मूल्यांकन	शिक्षण व शिक्षार्जन में सुधार	विद्यार्थियों को फ़ीडबैक देना शिक्षा पद्धति में ज़रूरी बदलाव लाना	शिक्षण-शिक्षार्जन की पूरी प्रक्रिया के दौरान	शिक्षक	शिक्षक विद्यार्थी	नियम-संदर्भित	निम्न	समय ज़्यादा लगता है
मूल्यांकन ही सीख	विद्यार्थियों में सीखने की क्षमता में सुधार	स्व-निगरानी स्व-निर्णय स्व-संशोधन	शिक्षण-शिक्षार्जन की पूरी प्रक्रिया के दौरान	विद्यार्थी	विद्यार्थी	नियम-संदर्भित	निम्न	छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कर पाना चुनौतीपूर्ण

तालिका 1. मूल्यांकन के विभिन्न उद्देश्यों का संक्षेप

References

1. Andrade, H., & Valtcheva, A. (2009). Promoting learning and achievement through self-assessment. Theory into practice, 48(1), 12-19.
2. ASER Reports - ASER Centre. (n.d.). Annual Status of Education Report. Retrieved August 28, 2020, Retrieved from https://www.asercentre.org/p/51.html?p=61
3. Baker, E. L., Barton, P. E., Darling-Hammond, L., Haertel, E., Ladd, H. F., Linn, R. L., ... & Shepard, L. A. (2010). Problems with the Use of Student Test Scores to Evaluate Teachers. EPI Briefing Paper# 278. Economic Policy Institute.
4. Black, P., & Wiliam, D. (2005). Inside the black box: Raising standards through classroom assessment. Granada Learning.

5. Brookhart, S. M., & Nitko, A. J. (2014). Educational assessment of students. Pearson Higher Ed.
6. Freeman, R., & Lewis, R. (1998). Planning and implementing assessment. Psychology Press.
7. Gagne, R. M., & Beard, J. G. (1978). Assessment of learning outcomes. Advances in instructional psychology, 1, 261-294.
8. Government of Karnataka (n.d.) Census-based state achievement survey (CSAS). Bengaluru, Karnataka School Quality Assessment and Accreditation Council, Retrieved from, http://kseeb.kar.nic.in/docs/KSQAAC/CSAS_2017_Report.pdf
9. Government of India (2009). The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, New Delhi, Ministry of Education.
10. Government of India. (2017). Learning outcomes at elementary stage. New Delhi, Ministry of Education, Retrieved from, https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Learning_outcomes.pdf.
11. Government of India. (2020). New Education Policy (NEP 2020). New Delhi, Ministry of Education Retrieved from, https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
12. National Council for Educational Research and Training (2017). National Achievement Survey (NAS). Retrieved from http://nas.schooleduinfo.in/dashboard/nas_ncert
13. Government of Madhya Pradesh, (n.d.). ***प्रतिभा पर्व : प्रतिभा पर्व प्रबंधन प्रणाली..*** Retrieved from http://www.educationportal.mp.gov.in/PratibhaParv/default.aspx
14. OECD (2010), PISA 2009 Results: Executive Summary. Retrieved from https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46619703.pdf
15. Paris, S. G., & Ayres, L. R. (1994). Becoming Reflective Students and Teachers With Portfolios and Authentic Assessment (Psychology in the Classroom: A Series on Applied Educational Psy) (1st ed.). Amer Psychological Assn.
16. National Achievement Survey (NAS), http://nas.schooleduinfo.in/dashboard/nas_ncert
17. Annual Status of Education Report (ASER), https://www.asercentre.org/p/51.html?p=61
18. Karnataka, census-based state achievement survey (CSAS), http://kseeb.kar.nic.in/docs/KSQAAC/CSAS_2017_Report.pdf
19. Gunotsav, Gujarat, http://www.gunotsav.org/index.html
20. Pratibha Parv, Madhya Pradesh, http://www.educationportal.mp.gov.in/PratibhaParv/default.aspx
21. Aanchal Chomal, Shilpi Banerjee. A chain of falling numbers. Deccan Herald. May 11, 2019
22. Anupama Raj, Shilpi Banerjee. Mistaken identity of assessment. Deccan Herald. Nov 28, 2019
23. Sinha, S., Banerji, R., & Wadhwa, W. (2016). Teacher performance in Bihar, India: Implications for education. The World Bank.
24. McCormick, B., Walsh, C., Moore, R., Palai, R. K., Gogoi, M., & Pareek, S. (2014). TESS-India Baseline Report 2013: Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar: baseline study of teacher educators, teacher trainees, head teachers, teachers and students.

[i] इस आलेख को शिल्पी बनर्जी ने लिखा है। वे अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ़ कंटिन्यूइंग एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं। उनसे इस ईमेल पर सम्पर्क किया जा सकता है - shilpi.banerjee@azimpremjifoundation.org

इस आलेख का संदर्भ निम्न प्रकार दिया जा सकता है:

भारतीय सन्दर्भ में मूल्यांकन के उद्देश्य की बारीक पड़ताल, मूल्यांकन रिसोर्सेज़, अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय

भारतीय सन्दर्भ में मूल्यांकन के उद्देश्य की बारीक पड़ताल